भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1973
17 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में पीएसीएस, डेयरी, मत्स्य पालन और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां

1973 श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य में प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की है;
(ख) यदि हाँ, तो ओडिशा राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी, मत्स्य पालन और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय का पुरी जैसे जिलों को, जहाँ डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण सहकारी समितियों की मजबूत उपस्थिति है, किसी विशेष सहकारी विकास कार्यक्रम में शामिल करने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को "देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने" की योजना को स्वीकृति दी है। योजना में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (DIDF), नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (NPDD), प्रधान मंत्री मत्स्य योजना (PMMSY), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण(कन्वर्जेन्स) के माध्यम से अगले पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने वाली नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) या प्राइमरी डेयरी/फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना शामिल है। यह योजना नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

15 नवंबर, 2025 तक, इस योजना के तहत देश भर में कुल 30,083 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ/प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS), डेयरी/फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत की गई हैं, और 15,793 मौजूदा डेयरी और फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुदृढ़ किया गया है। अब तक, कुल 255,881 ग्राम पंचायतें (GPs) प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) द्वारा कवर की गई हैं ; 87,159 ग्राम पंचायतें डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कवर की गई हैं; और 29,964 ग्राम पंचायतें फिशरीस कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कवर की गई हैं। ओडिशा राज्य में कुल 2,039 नई बहुउद्देशीय (M)-PACS (1537 संख्या), डेयरी (451 संख्या) और फिशरीस (51 संख्या) कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत की गई हैं और 209 डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है। ओडिशा के पुरी जिले में 59 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 39 PACS, 13 डेयरी, 07 फिशरीज़ कोऑपरेटिव शामिल हैं।

डेयरी, मात्स्यिकी और हस्तशिल्प जैसे सुदृढ़ सहकारी क्षेत्रों वाले जिलों को सहकारी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, 2025 में परिकल्पित रोडमैप के अनुसार राष्ट्रव्यापी सहकारी विस्तार योजना/नेशनवाइड कोऑपरेटिव एक्सपेंशन प्लान के तहत लाभ मिलता है। सरकार ने पुरी समेत किसी जिला-विशिष्ट कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसने "देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने" के लिए एक व्यापक नेशनल प्लान शुरू किया है ताकि देश भर में प्रत्येक कवर ना किए गए पंचायत और गांव में सहकारी समितियों को स्थापित और सुदृढ़ किया जा सके ।

****